दैनिक जागरण
पुरुषार्थ और परिश्रम में ही जीत का मंत्र निहित है

और मजबूत हुए मोदी

नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भाजपा और उसका गठबंधन जैसी शानदार जीत हासिल करता दिख रहा उससे भारतीय राजनीति एक नया आयाम रचती दिख रही है। यह अर्से बाद है जब कोई बहुमत वाली सरकार और बड़े बहुमत से सत्ता में लौट रही है। मोदी सरकार बिना किसी भावनात्मक मुद्दे के सहारे सत्ता में वापसी करके यही बता रही है कि काम के आधार पर भी प्रचंड जीत पाई जा सकती है। पांच साल पहले मोदी के नेतृत्व में जब भाजपा ने अपने बलबूते बहुमत हासिल किया था तो बार-बार यह रेखांकित किया गया था कि यह तो संप्रग शासन के प्रति आम लोगों की नाराजगी और साथ ही नरेंद्र मोदी की ओर से किए गए अच्छे दिन के वायदे का असर है। पांच साल बाद अगर मोदी ने और अधिक बहुमत हासिल किया तो इसका सीधा मतलब है कि उन्होंने सत्ता विरोधी रुझान को मात दे दी। ऐसा तभी होता है जब जनता को यह यकीन हो जाए कि जो पांच साल में नहीं हो सका वह आने वाले समय में अवश्य होगा। इतने बड़े देश में जहां समस्याओं का अंबार हो और जहां कोई भी सरकार पांच साल में चाहकर भी सब कुछ नहीं कर सकती वहां सत्ता विरोधी प्रभाव को कम करना किसी करिश्मे से कम नहीं। अबकी बार भाजपा की झोली में अधिक सीटें दिख रही हैं तो इसका एक बड़ा कारण उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल में उसका बेहतर प्रदर्शन तो है ही, उन कई राज्यों में भी बढ़त हासिल करना है जहां उसे पिछली बार भी उल्लेखनीय जीत मिली थी। राजनीति में चुनावी सफलता मुश्किल से ही दोहराई जाती है, लेकिन मोदी के नेतृत्व में भाजपा ने यह काम कर दिखाया।

जब यह माना जा रहा था कि उत्तर प्रदेश और बिहार सरीखे राज्य जातिवादी राजनीति की ओर लौट सकते हैं तब अगर इस तरह की राजनीति करने वाले दलों के मेल-मिलाप से भी ऐसा नहीं हुआ तो इससे यही रेखांकित हो रहा है कि देश का मानस बदल रहा है। यह बदलना भी चाहिए, क्योंकि जाति के आधार पर किसी दल के पक्ष या विरोध में गोलबंद होना लोकतांत्रिक मूल्यों के अनुकूल नहीं। जातिवादी राजनीति के प्रति देश के बदलते मानस को प्रोत्साहित करना होगा, क्योंकि इससे एक तो जात-पांत के बजाय सरकारों के काम-काज के आधार वोट देने का सिलसिला कायम होगा और दूसरे, मजहबी आधार पर गोलबंदी को भी थामा जा सकेगा। वास्तव में ऐसा होने पर ही नए भारत का निर्माण आसानी से हो सकेगा। यह अच्छा है कि सत्ता में और मजबूती से लौटे मोदी अपनी नई पारी के लिए कमर कसे हुए हैं। यह जरूरी है, क्योंकि कई मोर्चों पर चुनौतियां उनका इंतजार कर रही हैं। उन्हें उनसे पार पाना ही होगा। इसी के साथ यह भी अपेक्षित है कि विपक्ष अपनी पराजय के मूल कारणों की छानबीन करने का काम ईमानदारी से करे। उसे यह समझ आए तो बेहतर कि विरोधी के प्रति जरूरत से ज्यादा नकारात्मक प्रचार उसके पक्ष में माहौल बनाने का काम करता है। इस बार ऐसा ही हुआ और इसका एक बड़ा प्रमाण कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी को अमेठी में मिली पराजय है।

बंगाल में जबर्दस्त जीत

पिछले पांच दशकों में भाजपा को देश के कई राज्यों में जीत मिली थी, लेकिन बंगाल एक ऐसा सूबा रहा जहां की जमीन पर कमल नहीं खिल पा रहा था। दो से अधिक सीटें पिछले 25 सालों में भाजपा बंगाल में नहीं जीत पाई थी, परंतु इस बार राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ के संस्थापकों में से एक डॉ. श्यामा प्रसाद मुखर्जी की जन्म भूमि पर पीएम नरेंद्र मोदी और भाजपा अध्यक्ष अमित शाह ने कमल खिला दिया। भाजपा की यह जीत काफी अहम है। क्योंकि बंगाल में कभी भी भाजपा का जनाधार नहीं रहा। 2014 में भाजपा को महज 17 फीसद वोट मिला था, परंतु इस बार भाजपा का वोट प्रतिशत 40 तक पहुंच गया। सबसे अहम यह है कि जिस बंगाल में लगातार 34 वर्षों तक लोग वामपंथ को विजयी बनाते रहे उसी धरती पर भाजपा इतनी जल्द वटवृक्ष बन कर उभरेगी इसका किसी को शायद ही गुमान था। माकपा ने भाजपा को बंगाल में कभी जड़ जमाने का मौका नहीं दिया। 1998 एवं 1999 में तृणमूल प्रमुख ममता बनर्जी ने भाजपा के साथ मिलकर चुनाव लड़ा था जिसमें भाजपा को 1998 में दो सीटें और 1999 में एक सीट मिली थी। इसके बाद भाजपा को दार्जिलिंग छोड़कर कहीं भी एक भी सीट नहीं मिल रही थी। 2014 में भाजपा को दार्जिलिंग एवं आसनसोल की सीटें मिली थी, परंतु इस बार उत्तर बंगाल से लेकर दक्षिण बंगाल और जंगलमहल तक में कमल खिला है। इस जीत के गंभीर मायने हैं जो 2021 के लिए अहम है। भाजपा नेता इस चुनाव में कहते आ रहे थे कि 2019 हाफ एवं 2021 में तृणमूल साफ। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने इस चुनाव में 2019 भाजपा फिनिश का नारा दिया था, परंतु यही नहीं एक भी सीट नहीं जितने देने का दंभ भी भरा था, लेकिन स्थिति उलट हो गई। एक बार फिर बंगाल में परिवर्तन का इतिहास दोहरा रहा है। वर्ष 2009 में इसी तरह से तृणमूल 19 सीटें जीती थी और 2011 में 34 वर्षों के वामपंथी शासन का अंत कर दिया था, परंतु अब वही इतिहास भाजपा दोहराने की ओर आगे बढ़ रही है। यह ममता के लिए गंभीर चिंता का विषय होगा, क्योंकि ममता मोदी को रोकने के लिए पूरी ताकत लगा रखी थीं। क्षेत्रीय दलों से लेकर कांग्रेस तक को एक मंच पर ले आई थीं, परंतु हालात नहीं बदले और उनका दांव उन्हीं पर उल्टा पड़ा।

मोदी मैजिक का रहस्य

डॉ. एके वर्मा

मोदी ने अपनी कार्यशैली से लोगों में यह विश्वास भरा कि वह सामान्य राजनीतिज्ञों के विपरीत स्वार्थ, परिवारवाद और भ्रष्टाचार से ऊपर उठ कर देश को विकास की राह पर ले जा रहे हैं

भारतीय लोकतंत्र में काफी समय के बाद ऐसा हुआ है जब किसी मजबूत सरकार की और मजबूती से वापसी हुई हो। हालांकि इसके पहले कांग्रेस के नेतृत्व में संप्रग सरकार ने दो कार्यकाल पूरे किए थे, लेकिन तब कांग्रेस को 2004 में केवल 145 सीटें एवं 26.5 प्रतिशत वोट और 2009 में 206 सीटें एवं 28.5 प्रतिशत वोट मिले थे। 2014 में भाजपा ने नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में राजग की सरकार बनाई। उसे अपने बलबूते पूर्ण बहुमत मिला था। उसे 282 सीटें और 31.5 प्रतिशत वोट मिले थे। इस चुनाव में अपने सुशासन और विकास के बलबूते भाजपा द्वारा 300 के करीब सीटें प्राप्त करना भारतीय राजनीति में एक अभूतपूर्व घटना है। क्या है इस अभूतपूर्व घटना का रहस्य? क्या है मोदी मैजिक का सबब? विपक्षी दलों द्वारा मोदी की संभावित विजय को ईवीएम विवाद और चुनाव आयोग की निष्पक्षता पर सवाल खड़े करके कमतर करने की कोशिश जरूर की जा रही है, लेकिन लोकतंत्र की यही तो खूबी है कि आप जनता को मूर्ख नहीं बना सकते। मोदी ने लोकसभा चुनाव 'गेम-थ्योरी' मॉडल पर लड़ा। जैसे खेल में जीत के लिए हमें अपना कौशल बढ़ाने के साथ प्रतिद्वंद्वी की कमजोरियों का भी फायदा उठाना होता है वैसे ही मोदी ने न केवल अपनी टीम को विचारधारा, संगठन, नेतृत्व, सुशासन और लोक-कल्याण के आधार सुदृढ़ किया, बल्कि विपक्ष की नकारात्मक, विचारधाराविहीन, एजेंडाविहीन और नेतृत्वविहीन राजनीति को निशाना बना जनता में अपनी पैठ बनाकर विजय सुनिश्चित की।

मोदी ने 2014 से ही अपनी सरकार को मजबूत टीम बनाया। ऐसा करके उन्होंने संप्रग के दौरान मनमोहन सिंह की कमजोर प्रधानमंत्री की छवि को दूर कर एक मजबूत, साहसिक और त्वरित निर्णय लेने वाले प्रधानमंत्री की छवि अर्जित की। यह छवि देश-विदेश में धूम मचाती रही। भले ही विपक्ष उन्हें ताने देता रहा हो, मगर जनता का आशीर्वाद उन्हें मिलता रहा। आम मतदाता का यही स्वरूप तो भारतीय लोकतंत्र की थाती है। 'मन-की-बात' कार्यक्रम द्वारा उन्होंने जनता से अपना जुड़ाव और सशक्त किया, लेकिन यह आसान नहीं था। इसके लिए मोदी ने विकास को ही अपनी विचारधारा के रूप में पेश किया। वास्तविक विकास का स्वरूप सबसे सेक्युलर होता है। वह न हिंदू देखता है न मुसलमान। मोदी ने यह सुनिश्चित किया कि विकास योजनाओं का लाभ सबको बिना भेद-भाव के मिले। भले ही राज्य स्तर पर भ्रष्टाचार का बोलबाला बना हुआ हो, फिर भी बिचौलियों को खत्म कर लाभार्थियों के खातों में सीधे पैसे डालने से गरीबों, वंचितों और उपेक्षितों को आशा की एक किरण दिखाई दी। मोदी पर 'जुमलेबाज' होने का इल्जाम राहुल गांधी और तमाम विपक्षी नेता लगाते रहे, लेकिन जिन गरीबों को मोदी की विकास योजनाओं का लाभ मिलने लगा उन्हें आरोप बेबुनियाद लगा। सामाजिक सुरक्षा और लोक कल्याण के जो भी कार्यक्रम मोदी सरकार ने शुरू किए वे जमीन पर स्पष्ट दिखाई दिए। महिलाओं का एक बड़ा तबका 'बेटी बचाओ-बेटी पढ़ाओ', शौचालय, सफाई और तीन-तलाक जैसे प्रयोगों की वजह से मोदी की ओर आकृष्ट हुआ।

अवधेश राजपूत

मोदी ने राजनीति में एक नया विमर्श गढ़ा। उन्होंने राजनीति को जातिवादी खांचे से निकल कर जनवादी अर्थात वर्गीय खांचे में डाल दिया है। आज समाज के तमाम वर्गों जैसे महिलाओं, पिछड़ों, दलितों और यहां तक कि मुस्लिमों का भी विश्वास मोदी में जगा है। 'सबका साथ-सबका विकास' जुमला नहीं, एक हकीकत बन गया है। इससे पार्टी के जनाधार में क्रांतिकारी परिवर्तन हुआ जिसमें भाजपा के परंपरागत मतदाताओं के साथ-साथ समाज के सभी वर्गों के नए मतदाता जुड़े। खास तौर से प्रथम बार और युवा मतदाता को मोदी सरकार की 'हाईटेक' कार्यप्रणाली बहुत प्रभावित कर रही है। आज से पांच वर्ष पूर्व जो मतदाता केवल 13 वर्ष के रहे होंगे वे मोदी के 'मन-की-बात' के द्वारा पांच वर्षों में उनसे 53 बार मिले। यह एक विलक्षण प्रयोग था जिसे हम स्मार्ट पॉलिटिक्स कह सकते हैं। राजनीति में सफलता का और कोई सूत्र नहीं। नेक इरादों के साथ केवल जनता से जुड़े रहिए, सफलता आपके कदम चूमेगी। यही काम हमारे जनप्रतिनिधि और नेता करने से बचते हैं। मोदी पांच वर्षों में हुए सभी विधानसभा चुनावों में अपनी पार्टी के एकमात्र सुपर स्टार प्रचारक रहे जिसकी वजह से भी वह जनता से जुड़े रहे। मोदी सरकार ने अपने पांच वर्षों के शासन की उपलब्धियों पर वोट मांगा।

सबसे प्रभावित करने वाली बात यह रही कि हर समय घोटालों और भ्रष्टाचार में घिरी रहने वाली कांग्रेसी सरकारों के विपरीत मोदी सरकार का कार्यकाल साफ-सुथरा रहा। हालांकि राहुल गांधी ने राफेल पर मोदी को घेरने की कोशिश की, लेकिन जनता ने उसे खारिज कर दिया। यह मानने के पर्याप्त कारण हैं कि राहुल ने जिस प्रकार मोदी के प्रति अमर्यादित भाषा इस्तेमाल की उससे जनता में राहुल के प्रति नाराजगी भर गई। उधर मोदी ने न केवल अपनी सरकार में भ्रष्टाचार पर 'जीरो-टालरेंस' की नीति अपनाई वरन पारदर्शिता, उत्तरदायित्व, फिजूलखर्ची पर लगाम लगाकर सुशासन का परिचय दिया। उन्होंने कुछ ऐसे सुधार किए कि केंद्र सरकार के कार्यालयों में गुणात्मक परिवर्तन दिखने लगा।

चुनाव जीतने के लिए संगठनात्मक मजबूती बहुत जरूरी है। भाजपा ने इस पर बहुत ध्यान दिया। जहां अन्य पार्टियों की न तो कोई स्पष्ट विचारधारा रही और न प्रतिबद्ध कैडर, वहीं भाजपा अध्यक्ष अमित शाह पूरे पांच वर्ष पार्टी का संगठनात्मक ढांचा मजबूत बनाने, उन्हें नए-नए तरह से सक्रिय रखने और उनकी क्षमताओं को सही प्रयोग करने में जुटे रहे। अन्य दलों के लोगों को यह सीखना चाहिए। मोदी-शाह ने भाजपा सरकार और संगठन को कर्मनिष्ठ योगी की भांति चलाया और इसी कारण उन्होंने 2014 से भी बेहतर प्रदर्शन किया। चुनावों में प्रचार की आक्रामकता और नेतृत्व का बहुत प्रभाव पड़ता है। मोदी ने अपनी कार्यशैली और जीवनशैली से लोगों में यह विश्वास भर दिया कि वह सामान्य नेताओं के विपरीत स्वार्थ, परिवारवाद और भ्रष्टाचार से ऊपर उठकर देश को विकास की राह पर ले जा रहे हैं। उन्होंने आतंकवाद के खिलाफ कड़े कदम उठाए और पाकिस्तान को बैक-फुट पर लाकर अंतरराष्ट्रीय स्तर पर उसके विरुद्ध समर्थन हासिल किया। उन्होंने चीन को भी मजबूर किया कि वह अजहर मसूद के मुद्दे पर भारत के साथ आए। इन कदमों से उनके प्रति जनता का विश्वास और बढ़ा।

मोदी को सशक्त प्रतिरोध नहीं मिला। मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ जहां हाल में कांग्रेस की सरकारें बनी वहां भी भाजपा की लहर दिखी। इसने कांग्रेस को ध्वस्त कर दिया। निःसंदेह भाजपा के लिए सबसे चौंकाने वाले नतीजे बंगाल और कर्नाटक के रहे, पर अभी भी दक्षिणी राज्यों केरल, तमिलनाडु, आंध्र और तेलंगाना में उसका मजबूत जनाधार नहीं। इस प्रचंड जनादेश में मोदी के लिए चुनौती भी बड़ी है। आगामी विधानसभा चुनावों के बावजूद उनकी सरकार से यही आशा रहेगी कि वह देश हित में कठोर निर्णय लेने में पीछे नहीं हटेंगे।

(लेखक राजनीतिक विश्लेषक एवं सेंटर फॉर द स्टडी ऑफ सोसायटी एंड पॉलिटिक्स के निदेशक हैं)

response@jagran.com

विपक्ष ने खुद तय की अपनी हार

सुरेंद्र किशोर

विपक्षी पार्टियां मोदी सरकार से ऐसे लड़ रही थीं मानो कोई किसी से अपनी निजी संपत्ति को लेकर झगड़ रहा हो

पिछले आम चुनाव में कांग्रेस की अभूतपूर्व हार के बाद शशि थरूर ने कहा था कि हमें सुनिश्चित करना होगा कि हम भाजपा का राष्ट्रवाद पर एकाधिकार कायम न रहने दें। हार की पड़ताल करने के लिए एके एंटनी समिति भी गठित हुई। समिति ने भी कांग्रेस की कई कमजोरियां गिनाते हुए उनमें सुधार की जरूरत को रेखांकित किया था। ऐसे अन्य सुझाव भी कांग्रेस नेतृत्व को दबे स्वर में मिलते रहे थे, परंतु नेतृत्व ने स्वार्थवश तमाम सुझावों को नजरअंदाज किया। कांग्रेस में आंतरिक लोकतंत्र रहा होता तो शायद सुधार के लिए दबाव भी पड़ता, पर कुछ नहीं हुआ। भ्रष्टाचार, वंशवाद, वोट बैंक और राष्ट्रीय हितों की उपेक्षा से बिगड़ी उसकी छवि में सुधार की कोई गुंजाइश नजर नहीं आती। नतीजतन कांग्रेस के पुनरुत्थान की संभावना इस चुनाव नतीजे ने लगभग समाप्त कर दी है। इसका एक और कारण नजर आ रहा है। नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में राजग सरकार भ्रष्टाचार विरोधी अभियान, राष्ट्रीय सुरक्षा और सबका साथ-सबका विकास की नीति पर चलती रही है। उसका उसे चुनावी लाभ मिला है। यदि नए कार्यकाल में मोदी सरकार इन सभी कार्यक्रमों को अधिक एकाग्रता से लागू करेगी तो फिर कांग्रेस या किसी अन्य दल के लिए जनता के बीच कितनी गुंजाइश बचेगी, यह कहना कठिन है।

कांग्रेस जैसी देशव्यापी पार्टी का इतना कमजोर और गैर-जिम्मेदार हो जाना स्वस्थ लोकतंत्र के लिए सही नहीं है, मगर इसके लिए खुद कांग्रेस की अंतर्निहित कमजोरियां ही जिम्मेदार हैं। कोई अन्य नहीं। जिस पार्टी के नेतृत्व को कोई कारगर चुनावी नारा तक गढ़ना नहीं आता उससे लोग अब क्या उम्मीद रखेंगे? वर्ष 2014 के आम चुनाव की हार के कारणों पर कांग्रेस ने आत्ममंथन नहीं किया और उल्टे उनकी अनदेखी ही करती रही। ऐसी स्थिति में वह यह चुनाव कैसे जीत सकती थी? जो चोर नहीं है, उसे चोर कहेंगे, जहां भ्रष्टाचार नहीं, वहां भ्रष्टाचार तलाशेंगे और भारत-पाक द्वंद्व को लेकर ऐसे -ऐसे बयान देंगे जो भारतीय जनता को रास नहीं आए तो भला कितने वोट मिल सकते हैं? पिछले आम चुनाव में हार के बाद एंटनी समिति ने कहा था कि लोगों में यह धारणा बनी कि कांग्रेस अल्पसंख्यकों के प्रति ज्यादा झुकी है, इसीलिए बहुसंख्यक मतदाता भाजपा की ओर झुके। एंटनी के अनुसार भ्रष्टाचार, मुद्रास्फीति और अनुशासनहीनता हार के अन्य कारण थे। हालांकि अपनी इस रिपोर्ट में एंटनी ने यह नहीं बताया कि कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी को एक परिपक्व नेता के रूप में अभी विकसित होना शेष है। जिस तरह 1971 के भारत-पाक युद्ध के समय जनसंघ नेता अटल बिहारी वाजपेयी ने प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के नेतृत्व की तारीफ की थी उसी तरह बालाकोट में एयर स्ट्राइक के बाद कांग्रेस ने मोदी सरकार का समर्थन किया होता तो पार्टी की ऐसी दुर्गति नहीं होती। अपनी राज्य सरकारों के माध्यम से कांग्रेस भ्रष्टाचार के मोर्चे पर भी कुछ बेहतर संदेश दे सकती थी कि इस मुद्दे पर अब वह पहले जैसी नरम नहीं है। मगर ऐसा नहीं हुआ। उल्टे कांग्रेस के प्रथम परिवार पर भ्रष्टाचार के आरोपों से संबंधित मुकदमों को लेकर नए-नए खुलासे होते रहे।

पिछले आम चुनाव से पहले मणिशंकर अय्यर एआइसीसी स्थल पर मोदी के लिए टी-स्टाल खुलवा रहे थे। वही अय्यर 2019 के चुनाव से ठीक पहले मोदी के लेकर अपने 'नीच' वाले बयान को दोहरा रहे थे। कांग्रेस के कुछ अन्य नेताओं ने भी प्रधानमंत्री पर अमर्यादित टिप्पणियां जारी रखीं। भ्रष्टाचार के खिलाफ मुहिम छेड़ने वाले मोदी को लगातार चोर कहना भी राहुल गांधी को भारी पड़ा यानी कांग्रेस के सभी दांव खाली जा रहे थे। दूसरी ओर देश की अधिकांश जनता मोदी से इसलिए खुश थी कि उन्होंने पाकिस्तान को सबक सिखा दिया। ऐसे में चुनावी परिणाम की कल्पना पहले से ही की जा रही थी। अब बड़ा सवाल यही है कि कांग्रेस ने जो सियासी जमीन गंवाई है, क्या वह उसे कभी वापस हासिल कर पाएगी? आखिर सीमित वोट बैंक के कमजोर आधार पर कब तक राजनीतिक दल चल सकता है? इस चुनाव में भी अनेक मतदाताओं ने वोट बैंक से ऊपर उठकर मोदी के नाम पर राजग को वोट दिए। यह उन वंशवादी और खास वोट बैंक के आधार पर चलने वाले क्षेत्रीय दलों के अस्तित्व के लिए भी खतरे की घंटी है। वंशवाद की गाड़ी मुद्दों के ईंधन के बिना नहीं चल सकती। यदि कांग्रेस और परिवार से संचालित दलों ने अपने तौर-तरीके नहीं बदले तो उनका भविष्य शुभ नहीं कहा जा सकता। उन्हें इस पर ध्यान देना होगा कि आज का मतदाता राजनीति उन तौर-तरीकों को पसंद नहीं कर रहा जो एक दशक पहले तक प्रभावी माने जाते थे। बिहार में महागठबंधन की नाकामी और उत्तर प्रदेश में सपा-बसपा एवं रालोद गठबंधन के लचर प्रदर्शन ने यही बताया है कि जाति के आधार पर राजनीति करने वाले दल खुद को सेक्युलर बताकर जनता को और अधिक समय तक नहीं भरमा सकते।

मोदी के पूरे कार्यकाल में कांग्रेस और अन्य विपक्षी पार्टियां सरकार से ऐसे लड़ रही थीं मानो कोई किसी से अपनी निजी संपत्ति को लेकर झगड़ रहा हो। ऐसा करके वे अपनी हार की जमीन ही तैयार कर रही थीं। भाजपा विशेषकर मोदी पर अक्सर सांप्रदायिक होने का आरोप लगाने के लिए विपक्षी दलों ने इस तथ्य को जानबूझकर नजरअंदाज किया कि उनके पांच साल के कार्यकाल में देश में एक भी बड़ा दंगा नहीं हुआ। कांग्रेस और अन्य विपक्षी दलों ने यह भी देखने से इन्कार किया कि मोदी सरकार के किसी मंत्री पर भ्रष्टाचार का कोई आरोप नहीं लगा। इस मोर्चे पर मतदाताओं को राजग सरकार दूसरी अन्य सरकारों से अलग लगी और इसका नतीजा भी सबके सामने है। इस जनादेश ने मोदी सरकार को ताकत देते हुए उनकी जिम्मेदारी भी बढ़ा दी है। दो मोर्चों पर लोगों को उनसे और अधिक उम्मीदें हैं जिन्हें वही पूरा भी कर सकते हैं। एक तो यही कि सरकार देश को खंडित करने वालों और भ्रष्टाचारियों पर दोगुनी ताकत से हमला करे। इससे मतदाता अगली बार मोदी को और ज्यादा ताकत देंगे।

वर्ष 2014 में लाल किले की प्राचीर से मोदी ने देश को आश्वासन दिया था कि हम न खाएंगे और न खाने देंगे। इससे लोगों की उम्मीदें काफी बढ़ गई थीं। उन्होंने उम्मीदों के एक हिस्से को पूरा भी किया। दूसरे हिस्से को भी पूरा करने की राह में जो बाधाएं रही हैं, वे आजादी के बाद के सत्तर साल की देन है। काई जमी हुई है। अब इसे भी हटाना होगा। जहां तक विपक्ष की बात है, उसके पास पराजय के सही सबक सीखने के अलावा और कोई उपाय नहीं।

(लेखक राजनीतिक विश्लेषक एवं वरिष्ठ स्तंभकार हैं)

response@jagran.com

ऊर्जा

सुख

मानव जैसे विकसित प्राणी के लिए सुख प्राप्ति की लालसा स्वाभाविक है। सुख प्राप्ति की चेष्टा प्रत्येक मनुष्य करता है। वह जीवन रूपी घड़ी की सुई की तरह क्रियाशील रहता है। क्रियाशील न रहने वाला मनुष्य जीवित रहते हुए भी मृत्यु के समान है। सुख का आधार मनुष्य की मनःस्थिति पर आधारित है। भिन्न-भिन्न मनःस्थिति के मनुष्यों में भी सुख की सामग्रियां भिन्न-भिन्न होती हैं। नशा करने वाले मनुष्य के लिए नशा सुख प्रदान करता है, लेकिन जो नशे की विभीषिका से परिचित हैं, वे उससे दूर रहने में ही सुख की अनुभूति करते हैं। प्रभु ने जितनी सुख-सुविधाएं व्यक्ति को प्रदान की हैं, उतनी अन्य किसी जीव को नहीं। व्यक्ति स्वविवेक से अपनी क्षमता एवं उपलब्धियों का प्रयोग ईश्वर की सृष्टि को सुंदर, सुखी एवं संपन्न बनाने में करे, इसीलिए उसे यह सब प्राप्त हुआ है। इसी आधार पर व्यक्ति एवं पशु में सीमा-रेखा निर्धारित है, तभी मनुष्य जीवन की उत्कृष्टता और सार्थकता सिद्ध होती है। मानवोचित सुख पशुओं के सुख से कुछ भिन्न अवश्य होना चहिए। भोग से सुख प्राप्त होता है वह इंद्रियों को तृप्त करता है। इंद्रियजन्य वासना एक छलावा मात्र है।

मनुष्य विवेकशील प्राणी है। वह अंतरात्मा की आवाज सुनता है। उसे सच्चा सुख सेवा एवं साधना में ही मिलता है। इससे बढ़कर कोई ऐसा कर्म नहीं जो मनुष्य को अपनी गरिमा का भान कराता हो। मेरे पास पर्याप्त भोजन है, इससे मेरी क्षुधापूर्ति सुखपूर्वक हो जाती है, किंतु इससे सदा के लिए भूख नहीं मिट जाती। मुझसे भी अधिक भूखा कोई है और उसे दो रोटी यदि दे दी जाए तो भूखे की आत्मा की तृप्ति देखकर जो आनंद प्राप्त होगा वही सच्चा सुख है। प्रभु ने इसी कारण मनुष्य को सामर्थ्य प्रदान की है कि वह इतना उपार्जित कर सकता है जिसके दसवें हिस्से में उसकी शारीरिक आवश्यकताएं पूरी हो जाती हैं। शेष जो भाग यदि वह उस समाज के हित में लोक मंगल के लिए प्रयुक्त करे, तभी वह सुख पा सकता है। अगर हम समाज का ऋण उतारने के लिए कुछ भी प्रयास न करें तो हम सच्चे अर्थों में सुखी नहीं हो सकते। त्याग, परोपकार एवं लोक-मंगल के लिए अपने स्वार्थों को छोड़कर हम किसी पर कृपा नहीं करते, बल्कि समाज के ऋण को उतारने का प्रयास करते हैं।

डॉ. विजय प्रकाश त्रिपाठी

मोदी की आर्थिक नीतियों पर मुहर

डॉ. जयंतीलाल भंडारी

उम्मीद है कि मोदी सरकार इस प्रचंड जनादेश का सम्मान करते हुए आर्थिक सुधारों की राह पर तेजी से आगे बढ़ेगी

17वीं लोकसभा के इन चुनावों में मोदी सरकार की जीत में आर्थिक कारकों को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। यदि हम चुनावों के इतिहास को देखें तो पाते हैं कि अलग-अलग समय में जमींदारी प्रथा की समाप्ति, बैंकों का राष्ट्रीयकरण, गरीबी हटाओ, रोजगार गारंटी, भूमि अधिग्रहण, किसान हित, भ्रष्टाचार मिटाओ जैसे मुद्दों ने चुनावों की दशा-दिशा तय की। पिछले पांच सालों के दौरान देश की जनता ने देखा कि अर्थव्यवस्था अभूतपूर्व ढंग से बढ़ी, विदेशी मुद्रा भंडार रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गया, जीएसटी सफलतापूर्वक लागू किया गया, नोटबंदी के जरिए कालेधन पर करारा प्रहार किया गया, निर्यात के मोर्चे पर उल्लेखनीय सफलताएं मिलीं, दुनिया के निवेशकों का भारत में विश्वास बढ़ा। इन सब कारकों ने देश के मतदाताओं को प्रभावित किया और वे यह कहते हुए दिखाई दिए कि मोदी के साहसिक कदम देश के लिए अच्छे हैं और आर्थिक रूप से मजबूत भारत ही दुनिया में अपना परचम बुलंद करने में सक्षम हो सकता है। नोटबंदी तथा जीएसटी की प्रारंभिक तकलीफों के बाद इनके दिखाई दे रहे लाभ तथा पाकिस्तान सहित दुनिया के कई देशों में महंगाई बढ़ने के बावजूद भारत में महंगाई नियंत्रित रहने का भी करोड़ों मतदाताओं पर अनुकूल प्रभाव पड़ा। वस्तुतः मोदी सरकार महंगाई को लेकर सतर्क भी रही और भाग्यशाली भी। भाग्यशाली इसलिए कि मोदी सरकार के कार्यकाल के पहले चार सालों में अंतरराष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतें घटीं और अंतिम साल में ही इनमें इजाफा देखा गया। इसके नतीजतन, भारत का तेल आयात बिल घटा, जिससे राजकोषीय घाटे की कम करने में मदद मिली और राजकोष की स्थिति सुधरने से बड़ी धनराशि बुनियादी क्षेत्र के विकास पर लगाई जा सकी।

भले ही मोदी सरकार अपेक्षित मात्रा में नौकरियों का सृजन न कर पाई हो, लेकिन उसने ऐसी नीतियां तैयार की, जिससे देश में स्वरोजगार बढ़े और बड़ी संख्या में ऐसे लोग रोजगार मांगने के बजाय रोजगार देने की स्थिति में पहुंचे। मोदी सरकार ने पिछले पांच साल में 17 करोड़ लोगों को मुद्रा योजना के तहत आसान ऋण देकर स्वरोजगार और उद्यमिता की तरफ आगे बढ़ाया। मोदी सरकार की नीतियों के चलते आयकरदाताओं की संख्या बढ़ी और कर संग्रह में अभूतपूर्व बढ़ोतरी हुई। इसके साथ ही किसानों को लाभांवित करने के लिए बनाई गई योजनाओं और गरीब किसानों के लिए 6 हजार रुपये प्रतिवर्ष उनके खातों में जमा करने की किसान सम्मान निधि योजना तथा विभिन्न कृषि पदार्थों के समर्थन मूल्यों में वृद्धि के कदमों को ग्रामीण मतदाताओं का समर्थन मिला।

उम्मीद है कि मोदी सरकार इस प्रचंड जनादेश का सम्मान करते हुए आर्थिक सुधारों की राह पर तेजी से आगे बढ़ेगी। नई मोदी सरकार से अपेक्षाएं यही हैं कि पिछले कार्यकाल के दौरान आर्थिक मोर्चे पर जो कुछ कसर रह गई हो, उसे पूरा करने की दिशा में वह ऐसी नीतियां तैयार करे, जिससे देश के किसान, युवा, उद्यमी समेत हर वर्ग लाभाविन्त हो और देश की अर्थव्यवस्था सुदृढ़ ढंग से आगे बढ़ते हुए विकास के नए प्रतिमान स्थापित करे।

(लेखक अर्थशास्त्री हैं)

मेलबाक्स

नई सरकार से उम्मीदें

नई सरकार की चुनौतियां शीर्षक से लिखे अपने लेख में धर्मकीर्ति जोशी ने नई सरकार के आगे आर्थिक व्यवस्था और महंगाई की चुनौतियों का वर्णन किया है। मेरा मानना है कि दृढ़ इच्छाशक्ति से नामुमकिन को मुमकिन बनाया जा सकता है और हर चुनौती से निपटा जा सकता है। दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र भारत में आज एक बार फिर से एक नई सरकार उम्मीद की किरणें लेकर आ गई है। चुनाव के समय गरीब और मध्यम वर्गीय परिवार के मतदाता लंबी-लंबी लाइनों में लगकर सरकार चुनने के लिए इस उम्मीद से हर बार लगते हैं कि उनकी चुनी हुई सरकार अच्छे दिन लाएगी, लेकिन अफसोस कि ऐसा बहुत ही कम होता है। इसमें कोई दोराय नहीं है कि जिस भी राजनीतिक पार्टी की सरकार सत्ता में आई उसने देश के विकास में अपना योगदान दिया है। आज हमारे देश की गिनती भी विकास की ओर बढ़ते देशों में की जाती है, लेकिन फिर भी हमारे देश की सरकारों और राजनीति में कुछ कमियां तो जरूर हैं जिस कारण आज देश में भ्रष्टाचार चरम सीमा पर पहुंच गया है। देश को पहले मुगलों ने, फिर अंग्रेजों ने कमजोर किया और अब कुछ अपने ही इसे आर्थिक रूप से कमजोर कर रहे हैं। मौजूदा समय में हमारे देश की मुद्रा और अमेरिकी डॉलर में जो जमीन-आसमान का अंतर आ गया है, उसका कारण भ्रष्टाचार ही है। अब फिर से सत्ता में आई मोदी सरकार से यही उम्मीद है कि यह ऐसे कोई फैसले बिना तैयारी के न ले, जिससे उद्योग-धंधों पर कोई नकारात्मक असर पड़े, किसी का रोजगार छिने और न ही देश की अर्थव्यवस्था पटरी से उतरे। देश की अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ करने के लिए सरकार को भारतीय बाजार को दूनिया के दूसरे देशों में मजबूत करने और वहां व्यापार बढ़ाने के लिए चुस्ती दिखानी होगी और स्वदेशी पर भी जोर देना होगा। देश के अच्छे दिन लाने और गरीबी, बेरोजगारी या फिर महंगाई से देश को आजाद करने के लिए जनसंख्या पर नियंत्रण भी जरूरी है। इसके लिए देश के नागरिकों को भी जागरूक होना पड़ेगा।

raju09023693142@yahoo.com

अब जनसेवा की बारी

माननीयों ने जिस तत्परता, उत्साह, सजगता और कठिन परिश्रम से चुनाव में जी-जान लगाकर प्रचार-प्रसार किया, वह काबिल-ए-तारीफ है। उम्मीद है कि चाहे पक्ष हो या विपक्ष, यही जज्बा और जुनून देशसेवा-जनसेवा करने में और अपनी घोषणाओं को पूरा करने में भी दिखाएंगे। नेताओं के लिए सत्ता प्राप्ति का ध्येय, महज एक पड़ाव है। देशसेवा सर्वोपरि है जो अपनी कथनी-करनी को एक करके दिखाने से ही संभव है। जिस तरह चुनाव में पैसा पानी की तरह बहाया गया, उससे पता चलता है कि कोई भी दल गरीब नहीं है। वे योजनाओं को अपने बलबूते लागू करने और पूरा करने में सक्षम हैं, तो फिर चाहे सरकार किसी की भी बने, सबको मिलकर देश के उद्धार में लग जाना चाहिए। हर चुनाव में केवल काम बोलता है।

sonimohit895@gmail.com

सकते में विपक्ष

चुनाव के नतीजे से जहां भ